एक नजर

हत्या मामले में राहत, हाई कोर्ट ने फांसी की सजा को उम्रकैद में बदला

स्वतंत्र चेतना

नैनीताल। उच्च न्यायालय ने हत्या के मामले में 12 जून 2025 को सत्र न्यायाधीश प्रथम अपर जिला न्यायाधीश रुड़की जिला हरिद्वार द्वारा आरोपित हैदर को दी गई फांसी और रिहान को दी गई आजीवन कारावास की सजा की पुष्टि के लिए निचली अदालत द्वारा भेजे गए आदेश पर सुनवाई की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को पलटते हुए हैदर की फांसी की सजा को आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया है।पूर्व में कोर्ट ने अपील में दायर जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद उनकी जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए अपील पर सुनवाई के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया गया था।न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी एवं न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार मृतका का जघन्य अपराध करने वाले हैदर को निचली अदालत ने 12 जून 2025 को फांसी की सजा और पचास हजार रुपए के जुमार्ने से दंडित किया था। जुमार्ना अदा नही करने पर एक वर्ष का सश्रम कारावास से दंडित किया। मृतिका का भाई दिनेश ने वर्ष 2021 में थाना गंगनहर तहसील रुड़की जिला हरिद्वार में प्रार्थना देकर कहा कि उनकी बहन को हैदर अक्सर परेशान करता है, जब वे घर पर नही थे उस दिन वह अपने दो अन्य साथियों के साथ घर में घुसा, उसके बाद तीनों ने उसके घुटने मोड़कर पेपर कंटिग के धारदार हथियार से गला धड़ से अलग कर दिया।

आरोपित अक्सर उसपर शादी करने का दबाव डाल रहा था। बहन ने जब मना किया तो उसने यह कारनामा किया। निचली अदालत में हुई सुनवाई के दौरान कुल 13 गवाह पेश किए गए। आरोपित की तरफ से कहा गया कि वह निर्दोष है, फांसी की सजा देने योग्य नहीं जबकि अभियोजन पक्ष की तरफ से कहा गया कि इस घटना में आरोपित ने एक सोची समझी साजिश के तहत घटना को अंजाम दिया है। इसके अन्य साथियों ने भी इसका सहयोग किया है।

दूरस्थ क्षेत्रों में 24 नए उप शिक्षा अधिकारियों की तैनाती

स्वतंत्र चेतना

देहरादून। विद्यालयी शिक्षा विभाग को 24 नए उप शिक्षा अधिकारी मिले हैं। राज्य लोक सेवा आयोग से चयनित इन अधिकारियों को प्रथम चरण में प्रदेश के दूरस्थ विकासखंडों में तैनाती दी गई है। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के अनुमोदन के बाद तैनाती आदेश जारी किए गए। विभाग के अधिकारियों के अनुसार लोक सेवा आयोग के माध्यम से कुल 48 उप शिक्षा अधिकारियों का चयन हुआ है। सभी विभागीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षणरत हैं। प्रथम चरण में 24 अधिकारियों को पौड़ी, नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, टिहरी, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी जिले के विभिन्न विकासखंडों में भेजा गया है। पौड़ी में बिनीता रावत को द्वारीखाल, राज कुमार सिंह डसीला को बीरोंखाल, भावना चाहल को जयहारीखाल, कुणाल सिंह को पाबौं, शुभम गुप्ता को खिर्सू, मनीष मोहन नेगी को यमकेश्वर, राजेश परमार को थलीसैण, दीपक लखेड़ा को एकेश्वर और उमेश चंद्र सुयाल को कल्जीखाल की जिम्मेदारी दी गई है। नैनीताल में प्रवीण दिगारी को ओखलकांडा और परवीन अजहर को रामगढ़, अल्मोड़ा में राविन्स को सल्ट, अमित राणा को लमगड़ा और मनोज सिंह को भिकियासैंण तैनात किया गया है। चमोली में अंशिका बिष्ट को नंदानगर और रूबी नेगी को नारायणबगड़ भेजा गया है। टिहरी में दिव्या जोशी को देवप्रयाग, आशुतोष राणा को जाखणीधार, आयुष बंधानी को प्रतापनगर और समीक्षा उनियाल को थौलधार की जिम्मेदारी दी गई है। पिथौरागढ़ में राहुल सिंह रैंसवाल को कनालीछीना, बलवंत नाथ को मूनाकोट और योगेंद्र कुमार शर्मा को मुनस्यारी तथा उत्तरकाशी में राजन सिंह ठाकुर को पुरोला विकासखंड में तैनाती मिली है। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि शेष प्रशिक्षणरत उप शिक्षा अधिकारियों को भी जल्द तैनाती दी जाएगी। उनके अनुसार नए अधिकारियों की तैनाती से दूरस्थ क्षेत्रों की शिक्षा व्यवस्था मजबूत होने के साथ विभागीय और प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी।

राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री ने गांधी और शास्त्री को दी श्रद्धांजलि, आदर्शों को अपनाने का किया आह्वान

स्वतंत्र चेतना

देहरादून। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि.) और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर दोनों महान विभूतियों का स्मरण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने प्रदेशवासियों से गांधी और शास्त्री के आदर्शों को आत्मसात करते हुए सशक्त, आत्मनिर्भर और समरस भारत के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। जयंती की पूर्व संध्या पर गुरुवार को जारी अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा कि महात्मा गांधी का जीवन सत्य, अहिंसा, सादगी और सेवा का संदेश देता है। उनके विचार आज भी शांति, सद्भाव और मानवता के लिए प्रासंगिक हैं। उन्होंने कहा कि गांधी जी ने दृढ़ संकल्प, नैतिक साहस और अहिंसा के माध्यम से बड़े सामाजिक परिवर्तन का मार्ग दिखाया। राज्यपाल ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जीवन को सादगी, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और राष्ट्रसेवा की प्रेरणा बताया। उन्होंने कहा कि शास्त्री जी का ह्यजय जवान-जय किसानह्ल का संदेश देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के महत्व को रेखांकित करता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि महात्मा गांधी ने सत्य, अहिंसा, प्रेम, सद्भाव और मानवता के मूल्यों को अपने जीवन का आधार बनाया। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को जन-आंदोलन का स्वरूप देते हुए देशवासियों में स्वाधीनता, स्वाभिमान और एकता की भावना को मजबूत किया। धामी ने लाल बहादुर शास्त्री का स्मरण करते हुए कहा कि उनका जीवन सादगी, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा, नैतिकता और राष्ट्रसेवा के प्रति समर्पण का उदाहरण है। कठिन दौर में उनके नेतृत्व ने देश के आत्मविश्वास को मजबूत किया। ह्यजय जवान, जय किसानह्ल का उनका संदेश सैनिकों और किसानों के योगदान के महत्व को रेखांकित करता है। मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेशवासियों से गांधी जी के सत्य, अहिंसा और स्वच्छता के संदेश को जीवन में अपनाने तथा राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया।

वन्यजीव सप्ताह-2026 शुरू, मानव-वन्यजीव संघर्ष कम करने पर जोर

वन्यजीव संघर्ष में साहस दिखाने वाले 18 लोग सम्मानित, 51-51 हजार देने की घोषणा

स्वतंत्र चेतना

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को एफआर-आई परिसर में आयोजित कार्यक्रम में वन्यजीव सप्ताह-2026 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने मानव-वन्यजीव संघर्ष के दौरान साहस का परिचय देते हुए दूसरों की जान बचाने वाले 18 लोगों को सम्मानित किया और प्रत्येक को 51 हजार रुपये की धनराशि देने की घोषणा की।



मुख्यमंत्री ने विभिन्न स्टॉलों और वन्यजीव फोटोग्राफी पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने वन्यजीव विषय पर आयोजित निबंध प्रतियोगिता के विजेता छात्र-छात्राओं को भी सम्मानित किया। धामी ने अधिकारियों को प्रत्येक जिले में कम से कम एक नए पर्यटन स्थल की पहचान कर प्राकृतिक स्वरूप को सुरक्षित रखते हुए पर्यटकों के लिए सुविधाएं विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी में चिड़ियाघर की परिकल्पना को सरकार ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है और इस दिशा में तेजी से कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की प्राकृतिक संपदा और जैव विविधता उसकी प्रमुख पहचान है। सरकार की प्राथमिकता प्रकृति के साथ संतुलन बनाते हुए वन्यजीव पर्यटन और इको-टूरिज्म को बढ़ावा देना है, ताकि वन संरक्षण के साथ स्थानीय लोगों की आय और रोजगार के अवसर भी बढ़ें। उन्होंने उच्च हिमालयी क्षेत्रों में स्नो लेपर्ड पर्यटन की संभावनाओं पर भी कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से राजाजी टाइगर रिजर्व में बाघों के पुनर्स्थापन परियोजना का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है। मानव-वन्यजीव संघर्ष कम करने के लिए जंगलों की निगरानी व्यवस्था मजबूत की जा रही है। कॉर्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व में स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के गठन की दिशा में भी निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने वन्यजीव संरक्षण में स्थानीय लोगों की भागीदारी को जरूरी बताते हुए कहा कि सरकार इको-टूरिज्म के माध्यम से जंगलों के आसपास रहने वाले लोगों के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाने पर काम कर रही है।

उन्होंने कहा कि ह्यसीएम यंग ईको-प्रिन्योरह्ल के माध्यम से युवाओं को नेचर गाइड, ड्रोन पायलट, वन्यजीव फोटोग्राफी और इको-टूरिज्म जैसे क्षेत्रों में कौशल और रोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वन्यजीव हमले में मृत्यु होने पर दी जाने वाली अनुग्रह राशि छह लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये की गई है। वन्यजीव हमले में घायल नागरिकों के उपचार का खर्च भी राज्य सरकार वहन कर रही है। उन्होंने पर्यटकों से जंगल सफारी, राष्ट्रीय उद्यान और धार्मिक स्थलों में स्वच्छता बनाए रखने, प्लास्टिक न छोड़ने और वन्यजीवों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि उत्तराखंड में वन्यजीव संरक्षण और लोगों की आजीविका दोनों महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि वन्यजीवों की सुरक्षा सामूहिक जिम्मेदारी है। इस वर्ष की थीम ह्यजुड़े आवास-वन्य जीवन का विकासह्ल है। मानव-वन्यजीव संघर्ष कम करने के लिए विभिन्न वन्यजीव कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में विधायक सविता कपूर, राजीव तलवार, मीडिया सलाहकार समिति के अध्यक्ष प्रो. गोविंद बिष्ट, प्रमुख सचिव वन आरके सुधांशु, प्रमुख वन संरक्षक (हॉफ) कपिल लाल, प्रमुख वन संरक्ष-ाक (वन्यजीव) एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक नीना गैरवाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

हरिद्वार में ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज को मंजूरी, हर बैच में 50 एमबीबीएस सीटें

स्वतंत्र चेतना

देहरादून, 01 अक्टूबर (हि.स.)। हरिद्वार में ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज की स्थापना का रास्ता साफ हो गया है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने मेडिकल कॉलेज को मंजूरी दे दी है। कॉलेज में प्रत्येक बैच में 50 एमबीबीएस छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा। मौजूदा ईएसआईसी अस्पताल के बुनियादी ढांचे और उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए मेडिकल कॉलेज शुरू किया जाएगा।



मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेडिकल कॉलेज को मंजूरी मिलने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि केंद्र के सहयोग से उत्तराखंड में स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में लगातार कार्य हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरिद्वार में मेडिकल कॉलेज शुरू होने से चिकित्सा शिक्षा के अवसरों का विस्तार होगा और क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं को भी मजबूती मिलेगी। मौजूदा ईएस-ाआईसी अस्पताल के बुनियादी ढांचे के इस्तेमाल से उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित होगा और चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने में मदद मिलेगी। ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज की स्थापना को मंजूरी 30 जून, 2026 को नई दिल्ली स्थित ईएसआईसी मुख्यालय में हुई निगम की 198वीं बैठक में लिए गए निर्णय के क्रम में दी गई है। इसके तहत हरिद्वार में पहले से उपलब्ध ईएसआईसी अस्पताल के संसाधनों और ढांचे को मेडिकल शिक्षा के लिए उपयोग में लाया जाएगा। मेडिकल कॉलेज की स्थापना से उत्तराखंड में चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में एक नया विकल्प जुड़ने के साथ एमबीबीएस की 50 सीटें उपलब्ध होंगी। इससे राज्य के विद्यार्थियों को चिकित्सा शिक्षा के लिए एक और संस्थान मिलेगा। साथ ही अस्पताल से जुड़े मौजूदा स्वास्थ्य ढांचे का उपयोग व्यापक स्तर पर किया जा सकेगा।

रामपुर तिराहा कांड के बलिदानियों को मुख्यमंत्री ने किया नमन

कहा- उनके सपनों का उत्तराखंड बनाना जिम्मेदारी

स्वतंत्र चेतना

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुजफ्फरनगर कांड (रामपुर तिराहा) की बरसी की पूर्व संध्या पर उत्तराखंड राज्य आंदोलन के अमर बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि अलग राज्य के लिए आंदोलनकारियों का संघर्ष, त्याग और बलिदान उत्तराखण्ड की नींव का महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रदेशवासी उनके योगदान को सदैव श्रद्धा और सम्मान के साथ याद करते रहेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड को अलग राज्य का दर्जा दिलाने के लिए आंदोलनकारियों ने लंबे समय तक संघर्ष किया और अनेक लोगों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। उन्हीं के संघर्ष और बलिदान से उत्तराखण्ड राज्य का गठन संभव हुआ। उन्होंने कहा कि शहीदों की भावनाओं और आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप राज्य का निर्माण करना सरकार और समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड के संतुलित और सर्वांगीण विकास के लिए लगातार काम कर रही है। दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल और रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाओं का विस्तार करने के साथ युवाओं, महिलाओं, किसानों और स्थानीय लोगों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की प्रगति के लिए विकास के साथ संस्कृति, परंपराओं, प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण का संरक्षण भी जरूरी है। उत्तराखंड को आदर्श एवं अग्रणी राज्य बनाने के लिए राज्य आंदोलन की मूल भावना को विकास कार्यों में प्रतिबिंबित करना होगा। उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलन के अमर शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उनके सपनों के उत्तराखण्ड के निर्माण के लिए पूरी निष्ठा, ईमानदारी और एकजुटता से काम किया जाए। उन्होंने प्रदेशवासियों से राज्य की उन्नति और समृद्धि में अपना योगदान देने का आह्वान किया।

महिला मोर्चा को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर जोर

राष्ट्रीय अध्यक्ष रूपकुमारी ने लिया संगठनात्मक फीडबैक

स्वतंत्र चेतना

देहरादून। भाजपा महिला मोर्चा की नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं महासमुंद की सांसद रूपकुमारी चौधरी ने अपने प्रथम उत्तराखंड दौरे के दौरान गुरुवार को देहरादून में महिला मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ संगठनात्मक बैठक की। नगर निगम टाउन हॉल में आयोजित बैठक में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, महिलाओं से निरंतर संवाद और केंद्र तथा राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी पात्र लोगों तक पहुंचाने पर चर्चा हुई।



इससे पहले उन्होंने फनवैली स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में आयोजित ह्यआंगन मिलन सेवाह्ल कार्यक्रम में हिस्सा लिया और आंगनबाड़ी कार्यकताओं को सम्मानित किया। इसके बाद नगर निगम टाउन हॉल में प्रेस वार्ता और परिचयात्मक बैठक हुई। रूपकुमारी चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि महिला मोर्चा की भूमिका संगठनात्मक गतिविधियों के साथ महिलाओं के बीच संवाद स्थापित करने और उन्हें सरकारी योजनाओं और अधिकारों के प्रति जागरूक करने की भी है। उन्होंने महिला कार्यकताओं से बूथ स्तर तक सक्रियता बढ़ाने और महिलाओं के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि महिला उद्यमिता,कौशल विकास,स्वयं सहायता समूहों और महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण से जुड़े विषयों पर संगठन को काम करना चाहिए। पार्टी की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, उन्होंने महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने और संगठनात्मक गतिविधियों को मजबूत करने पर जोर दिया। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत करते हुए कहा कि प्रदेश में महिलाओं को स्वरोजगार, कौशल विकास, स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग एवं विपणन और स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने के लिए संगठन स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। बैठक में महिला मोर्चा के आगामी कार्यक्रमों, संगठनात्मक विस्तार और बूथ स्तर पर महिला कार्यकताओं की सक्रिय भागीदारी सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रदेश पदाधिकारियों और कार्यकताओं से संगठनात्मक गतिविधियों की जानकारी भी ली। कार्यक्रम में देहरादून नगर निगम के महापौर सौरभ थपलियाल, महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष एवं प्रभारी शैलेंद्र बिष्ट, महानगर अध्यक्ष सुमन सिंह, प्रदेश महामंत्री हिमानी वैष्णव और रश्मि रस्तोगी, राज्यमंत्री मधु भट्ट समेत पार्टी एवं महिला मोर्चा के पदाधिकारी मौजूद रहे।

हत्या और आगजनी मामले में उम्रकैद रद्द, हाई कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में किया बरी

स्वतंत्र चेतना

नैनीताल। उच्च न्यायालय ने हत्या, आगजनी और साक्ष्य मिटाने के मामले में निचली अदालत से मिली उम्रकैद की सजा को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई के बाद निचली अदालत के फैसले को रद्द करते हुए अपीलकताओं को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है

न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।

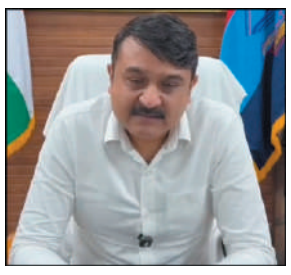
मामले के अनुसार सत्र न्यायालय रूद्रप्रयाग ने वर्ष 2018 में अपीलकर्ता मुकेश थपलियाल को हत्या के अपराध में उसे आजीवन कारावास सहित अन्य धाराओं में सजा सुनाई थी। अभियोजन के अनुसार 27 अगस्त 2016 को विमला देवी की घर में आग लगने से मौत हो गई थी। जांच के दौरान अभियोजन ने अपीलकर्ता पर हत्या और घर में आग लगाने का आरोप लगाया था। इस मामले में 11 गवाह पेश किए गए थे।

साइबर अपराध से बचाव के लिए उत्तराखंड एसटीएफ की नई पहल

विकसित किया साइबर पोर्टल हब

स्वतंत्र चेतना

देहरादून। उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने साइबर अपराध से जुड़ी शिकायतों और सहायता सेवाओं तक आमजन की आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए साइबर पोर्टल हब विकसित किया है। इस पोर्टल पर साइबर अपराध, ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी, महिला एवं बच्चों की साइबर सुरक्षा, सोशल मीडिया और डिजिटल भुगतान से संबंधित महत्वपूर्ण आधिकारिक सेव-ाओं के लिंक एक ही स्थान पर उपलब्ध कराए गए हैं।



एसटीएफ की ओर से गुरुवार को जारी विज्ञप्ति के अनुसार साइबर पोर्टलहबडॉटओआरजी के माध्यम से नागरिक राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) तक सीधे पहुंच सकते हैं। इसमें महिला और बच्चों से संबंधित साइबर अपराध की शिकायत दर्ज करने के लिए उपलब्ध विकल्पों की जानकारी भी दी गई है। पोर्टल पर बच्चों से संबंधित आपत्तिजनक अथवा यौन शोषण सामग्री के ऑनलाइन प्रसार की स्थिति में रिपोर्टिंग के लिए एनसीआरपी और टेक इट डाउन जैसी सेवाओं की जानकारी उपलब्ध कराई गई है। वहीं, वयस्कों की बिना सहमति साझा की गई निजी तस्वीरों और वीडियो के मामलों में स्टॉप एनसीआईआई जैसी सेवा की जानकारी भी दी गई है। एसटीएफ ने साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की स्थिति में नागरिकों से तत्काल 1930 साइबर अपराध हेल्पलाइन पर सूचना देने की अपील की है।

पोर्टल पर भारतीय रिजर्व बैंक की शिकायत एवं निवारण सेवाओं, उपभोक्ता शिकायत, डिजिटल भुगतान और यूपीआई से संबंधित आधिकारिक सेवाओं के लिंक भी उपलब्ध हैं। साइबर पोर्टल हब में सोशल मीडिया खाते के हैक होने, फर्जी प्रोफाइल बनाने, किसी अन्य व्यक्ति के नाम से खाता संचालित किए जाने और खाता वापस पाने जैसी समस्याओं के लिए विभिन्न सोशल मीडिया मंचों के आधिकारिक शिकायत एवं रिपोर्टिंग माध्यमों के लिंक भी शामिल किए गए हैं। इसके अलावा बैंकिंग, दूरसंचार, ई-कॉमर्स और अन्य ऑनलाइन सेवाओं के आधिकारिक लिंक तथा साइबर सुरक्षा और डिजिटल जांच से संबंधित कुछ उपयोगी उपकरण भी उपलब्ध कराए गए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ अजय सिंह ने कहा कि साइबर अपराध से बचाव और उसके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के लिए सही जानकारी के साथ समय पर उचित माध्यम से शिकायत करना महत्वपूर्ण है।

उन्होंने कहा कि पोर्टल का उद्देश्य नागरिकों को अलग-अलग वेबसाइटों पर जानकारी तलाशने की परेशानी से बचाते हुए महत्वपूर्ण आधिकारिक साइबर सुरक्षा, शिकायत और सहायता सेवाओं तक एक स्थान से पहुंच उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि एसटीएफ में कार्य के दौरान यह महसूस किया गया कि आमजन, विशेषकर कम डिजिटल जानकारी रखने वाले लोगों को साइबर अपराध से संबंधित सही पोर्टल और शिकायत प्रक्रिया की जानकारी नहीं होती। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ह्यसाइबर पोर्टल हबह्ल को एक सरल डिजिटल संदर्भ केंद्र के रूप में विकसित किया गया है।

NOTICE

THE GENERAL PUBLIC IS INFORMED THAT I HAVE CHANGED MY NAME FROM MOHAMMAD RIZWAAN TO RIZWAN HASAN AND IN FUTURE I SHOULD BE KNOWN AS RIZWAN HASAN S/O MAU UMAR,
ADDRESS : SULTANPUR, ADAMPUR, HARIDWAR, UTTARAKHAND

NOTICE

THE GENERAL PUBLIC IS INFORMED THAT I HAVE CHANGED MY NAME FROM SAURABHA KUMAR YADAVA TO SAURABH YADAV AND IN FUTURE I SHOULD BE KNOWN AS SAURABH YADAV S/O RAM CHANDRA,
ADDRESS : H.NO. 44 A, BAHADRABAD, HARIDWAR, UTTARAKHAND

NOTICE

THE GENERAL PUBLIC IS INFORMED THAT I HAVE CHANGED MY NAME FROM RAJESH KUMAR TO RAJESH KUMAR YADAV AND IN FUTURE I SHOULD BE KNOWN AS RAJESH KUMAR YADAV S/O RAM CHANDRA YADAV,
ADDRESS : H.NO. 44 A, VILL - BAHADRABAD, HARIDWAR, UTTARAKHAND, 249402

NOTICE

THE GENERAL PUBLIC IS INFORMED THAT I HAVE CHANGED MY NAME FROM GOPAL KRISHAN SHARMA TO GOPAL KRISHAN AND IN FUTURE I SHOULD BE KNOWN AS GOPAL KRISHAN S/O NARENDRA KUMAR SHARMA,
ADDRESS : DUTT KUTI, RK MISSION ROAD, KANKHAL, HARIDWAR, UTTARAKHAND

उत्तर रेलवे
ई–नीलामी
वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक / पीएस (ए.सी.ओ.) उत्तर रेलवे, मुरादाबाद मंडल द्वारा 13 गाड़ियों में ट्रेन साइड वेंडिंग (TSV) के कार्य को IREPS के माध्यम से ठेके पर देने हेतु ई–बोलियाँ दिनांक 19.10.2026 को आमंत्रित की जाती हैं। विस्तृत जानकारी, नियम एवं शर्तें www.ireps.gov.in पर उपलब्ध हैं।
3428/2026
ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

उत्तर रेलवे
ई–नीलामी
- मुरादाबाद मंडल से शुरू होने वाली ट्रेनों के 14 एस.एल.आरः

गाड़ी सं. 19610 (R-I), 12402 (R-I), 14314 (R-I), 19032 (F-I, R-I), 22918 (F-I), 14236 (F-I), 12912 (F-I), 14320 (F-I), 14318 (F-I), 14310 (F-I), 19020 (F-I), 12172 (F-I) & 14230 (F-I) के पार्सल स्पेस को लीज पर 3 साल की अवधि के लिए देने हेतु ई–नीलामी के तहत दिनांक 12.10.2026 (Timings : 10:00 am) को बोली के माध्यम से आमंत्रित की जाएगी। इसके लिए विस्तृत नियम और शर्तें www.ireps.gov.in वेबसाइट पर ही उपलब्ध हैं। 3408/26
ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

उत्तर रेलवे
ई–नीलामी
मुरादाबाद मंडल के शाहजहांपुर बरेली, मुरादाबाद, लक्सर, & ऋषिकेश स्टेशन के क्लॉक रूम को 5 साल के लिए संचालन और रखरखाव हेतु ई– नीलामी के तहत दिनांक 15.10.2026 (टाइम 11:00 am) को बोली आमंत्रित करने की जानी है। ई–नीलामी www.ireps.gov.in के माध्यम से आमंत्रित की जाएंगी। इसके लिए विस्तृत नियम और शर्तें वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
3410/2026
ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

उत्तर रेलवे
ई–नीलामी
मुरादाबाद मंडल के बरेली एवं मुरादाबाद स्टेशन पर "निर्गत पार्सल शेड के पास दोपहिया वाहनों की पैकिंग और अन्य पार्सल पैकिंग सेवा के लिए अनुबंध" पर 03 साल हेतु ई– नीलामी के तहत दिनांक 15.10.2026 टाइम 11:00 am को बोली www.ireps.gov.in के माध्यम से आमंत्रित की जाएंगी। इसके लिए विस्तृत नियम और शर्तें वेबसाइट पर ही उपलब्ध हैं। 3409/2026
ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
रजिस्टर्ड ऑफिसः 6वीं मंज़िल, बी बिल्डिंग, गागा टूनो, लोहेगांव, पुणे, महाराष्ट्र 411014
ब्रांच ऑफ यूनिटः दूसरी मंजिल, खसरा नं. 489 एम, 492/2एम, 491 एम, 498 एम, गणेशपुर, मालविये चौक, रुड़की, उत्तराखंड 247667

ई-ऑक्शन सेल नोटिस सरफेसी एक्ट के तहत सुरक्षित अचल संपत्ति की बिक्री

'सिक्योरिटाइज़ेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002' (जिसे आगे 'एक्ट' कहा जाएगा) और 'सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) रूल्स, 2002' के नियम 8 और 9 के तहत अचल संपत्ति की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना।

आम जनता और विशेष रूप से उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गिरवी रखने वाले/गारंटर को यह सूचना दी जाती है कि नीचे बताई गई अचल संपत्तियां 'ग्रिहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड' (जिसे एक्ट के अनुसार 'सिक्योर्ड क्रेडिटर' कहा जाएगा) के पास गिरवी रखी गई थीं। इन संपत्तियों का कब्जा 'सिक्योर्ड क्रेडिटर' के अधिकृत अधिकारी ने एक्ट की धारा 13(12) और 'सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) रूल्स' के नियम 8 और 9 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए और एक्ट की धारा 13(2) के तहत नोटिस के आधार पर लिया है। सिक्योर्ड एसेट्स (गिरवी रखी गई संपत्तियां) को 19-10-2026 को ई-नीलामी के जरिए "जैसा है, जहाँ है" (As is where is), "जैसा है, वैसा है" (As is what is) और "जो कुछ भी है" (Whatever there is) के आधार पर बेचा जाएगा। आम जनता को सूचित किया जाता है कि हम https://www.bankeauctions.com वेबसाइट पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से नीलामी आयोजित करने जा रहे हैं। बिक्री की विस्तृत शर्तों और नियमों (T&Cs) के लिए, कृपया GHFL/सिक्योर्ड क्रेडिटर की वेबसाइट www.grihumhousing.com पर दिए गए लिंक को देखें।

प्रस्ताव संख्या ग्राहक का नाम {ए}	मांग सूचना दिनांक और उत्कृष्ट राशि {बी}	कब्जे की प्रकृति {सी}	विवरण संपत्ति का {डी}	संरक्षित कीमत {ई}	ईएमडी (10% आरपी के) {एफ}	ईएमडी जमा करने की तिथि {जी}	वृद्धिशील बोली {एच}	संपत्ति निरीक्षण दिनांक एवं समय {क}	दिनांक और का समय नीलामी {जे}	ज्ञात अतिक्रमण-प्रतिबंध/अदालत मामले यदि कोई हों {के}
लोन नंबर HL0066510000 0005020836 मनोज कुमार (उधारकर्ता) शिल्पा शर्मा (सह-उधारकर्ता)	नोटिस की तारीख: 08-08-2025 कुल बकाया राशि: रु. 26,93,989/- (छब्बीस लाख तिरानवे हजार नौ सौ नवासी रुपये मात्र), जिसका भुगतान 08-08-2025 तक किया जाना है, साथ ही वसूली होने तक 12.85% सालाना की दर से ब्याज भी देय होगा।	भौतिक	जमीन के उस एक प्लॉट का पूरा हिस्सा,जिसकी माप पूर्व में 57 फीट, पश्चिम में 57 फीट, उत्तर में 41 फीट और दक्षिण में 41 फीट है और कुल क्षेत्रफल 2337 वर्ग फीट या 217.193 वर्ग मीटर है, जो कि खाता नंबर 43 खसरा नंबर 350/2 का हिस्सा है, और वार्ड नंबर 6, गाँव डंडेहरा (अभी नगर पंचायत डंडेहरा की सीमा में) परगना और तहसीलरुड़की, ज़िला हरिद्वार में स्थित है; इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं :-पूर्व:- पाल जी का घर। पश्चिम :- अहसान का प्लॉट। उत्तर :- 16 फीट चौड़ा रास्ता। दक्षिण :- अज्ञात व्यक्ति की जमीन।	रु. 18,60,837/- (अठारह लाख साठ हजार आठ सौ सैंतीस रुपये मात्र)	रु. 1,86,083.70/ (एक लाख छियासी हजार तिरासी रुपये और सत्तर पैसे मात्र)	16-10-2026 शाम 5 बजे से पहले	10,000/-	13-10-2026 (सुबह 11 बजे शाम 4 बजे)	19-10-2026 (सुबह 11 बजे दोपहर 2 बजे)	शून्य

बोली लगाने/खरीदने के इच्छुक लोगों को सलाह